

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

आपदा प्रबन्धन अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक ०३ फरवरी, 2016

**विषय:-** प्राकृतिक आपदा एस.पी.ए.(आपदा 2013) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड महिला एवं बाल विकास विभाग से सम्बन्धित कार्यों के पुनर्निर्माण/गतिविधियों हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-4332/XVIII-(2)/2014-4(38)/2014, दिनांक 26.09.2014 एवं आपके पत्र संख्या-349/203/आई.सी.डी.एस./2015-16 दिनांक 14 सितम्बर, 2015 के क्रम में महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्रावली संख्या-02(10)/2012 टी.सी. द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव ₹ 676.00 लाख के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2013 में आयी भीषण प्राकृतिक आपदा, बादल फटने एवं बाढ़ आदि के कारण भारत सरकार द्वारा आपदाग्रस्त जनपदों हेतु अनुमोदित विशेष योजनागत सहायता (एस.पी.ए.-आर) के अंतर्गत अवमुक्त धनराशि के सम्बन्ध में नियोजन विभाग के पत्र संख्या-1456/37-सी/रा.यो.आ./एस.पी.ए.-आर/2015-16 टी.सी., दिनांक 14.12.2015 के क्रम में आपदा प्रबन्धन विभाग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं हेतु उपलब्ध बजट व्यवस्था के सापेक्ष ₹ 666.00 उत्तराखण्ड महिला एवं बाल विकास समिति के अन्तर्गत Sustainable Livelihood Approach for Women and Adolescent Girls in Natural Disaster in Affected Area of SPA /Reconstruction & Cure help for the victims of Natural Disaster area SPA/Reconstruction Area के अन्तर्गत आपदा प्रभावित जनपद उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग एवं चमोली में उक्त योजनाओं के संचालन हेतु ₹ 666.00 लाख (छ: करोड़ छियासठ लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- वर्णित योजनाओं हेतु भारत सरकार द्वारा सी.एस.एस./केन्द्र पोषित योजनाओं के सम्बन्ध में निर्गत दिशा-निर्देश, मानकों एवं नियमों का पालन किया जायेगा तथा तत्काल सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
- 2- स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उन्हीं योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय, जिनके लिये यह स्वीकृति जारी की जा रही है तथा जिन योजनाओं की नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त है।
- 3- धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किस्तों में किया जायेगा।
- 4- धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा आंगणन पर तकनीकी स्वीकृति यदि आवश्यक हो अवश्य प्राप्त करा ली जायेगी। अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय कदापि न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिये न छोड़ी जाय।
- 5- उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त्युस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के सुसंगत प्राविधानों तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।
- 6- यह धनराशि आपदा 2013 से हुई क्षतियों के लिये है। अतः किसी भी दशा में जून, 2013 से पूर्व के कार्यों के लिये इस धनराशि का उपयोग नहीं किया जायेगा।
- 7- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष, आई0सी0डी0एस0/आहरण एवं वितरण अधिकारी अवमुक्त धनराशि का विवरण बी.एम.-10 पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार, उत्तराखण्ड, राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।
- 8- कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित विभागाध्यक्ष, आई0सी0डी0एस0/जिलाधिकारी/कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।



9- त्रैमासिक रूप से कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं व्यय विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा और स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2016 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।

10- विभागाध्यक्ष आई0सी0डी0एस0 द्वारा सक्षम अधिकारी के माध्यम से प्रश्नगत कार्यों का मासिक रूप से स्थल निरीक्षण समय-समय पर किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

11- आई.सी.डी.एस. विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के अनुसार ₹ 676.00 लाख के सापेक्ष वर्तमान में उपलब्ध बजट व्यवस्था के अनुसार ₹ 666.00 लाख की धनराशि एक मुश्त अवमुक्त की जा रही है, जिसकी कार्यों हेतु फॉट प्रमुख सचिव, आई.सी.डी.एस., उत्तराखण्ड शासन द्वारा अपने स्तर पर की जायेगी। शेष धनराशि आवंटन किये जाने हेतु विभाग द्वारा प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने पर यथा प्रक्रिया अवमुक्त की जायेगी।

12- उल्लिखित कार्यों/योजनाओं पर मानकानुसार यथाप्रक्रिया भारत सरकार आदि का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।

13- यदि उक्त कार्यों में से किसी कार्य हेतु आई0सी0डी0एस0 के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का समायोजन सुनिश्चित किया जायेगा तथा अतिरिक्त अवशेष धनराशि यदि कोई हो तो उसे शासन को समर्पित कर दिया जायेगा। स्वीकृत की जा रही योजनाओं के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की दोहराव (Duplicacy) की स्थिति के लिये विभाग के विभागाध्यक्ष पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।

14- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-6 के लेखाशीर्षक-2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना-0110-एस.पी.ए. (आपदा 2013) के अन्तर्गत महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास हेतु अनुदान-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

15- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-1172/XXVII(1)/2015, दिनांक 28 सितम्बर, 2015 में प्राप्त निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)  
सचिव

संख्या-291 (1)/XVIII-(2)/16-4(38)/2014, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) ओबैराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
- 2- प्रमुख सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- अपर सचिव, वित्त एवं व्यय अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- जिलाधिकारी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग एवं चमोली।
- 6- निदेशक, कोषागार, 23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
- 7- राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 8- प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 9- वित्त अनुभाग-1 एवं 5, उत्तराखण्ड शासन।
- 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)  
सचिव